यूएस वीजा प्रोसेस में देरी से कंपनियों पर असर

वर्क वीजा वाले कर्मचारियों को अमेरिका छोड़ने से रोक रहे गूगल, ऐप्पल

वाशिंगटन, 21 दिसंबर. अमेरिका में वीजा प्रक्रिया के नए नियमों के चलते अपॉइंटमेंट और प्रोसेसिंग में हो रही देरी का असर अब साफ दिखने लगा है.

खासतौर पर एच -1बी वीजा पर निर्भर टेक्नोलॉजी कंपनियों और विदेशी प्रोफेशनल्स को इसका सामना करना पड़ रहा है. नए वेटिंग प्रोसेस के तहत अब ऑनलाइन प्रेजेंस रिव्यू अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े जोखिमों की जांच की जाती है. हालांकि एप्लिकेंट अब भी केस-बाय-केस आधार पर जल्दी अपॉइंटमेंट की रिक्वेस्ट

कर सकते हैं और रिसोर्स में बदलाव होने पर स्लॉट बदले जा सकते हैं, लेकिन नए वेटिंग प्रोसेस ने पूरी प्रक्रिया को अधिक जटिल बना दिया है. नए सिस्टम के तहत आवेदकों की ऑनलाइन प्रेजेंस रिव्यू के जरिए स्क्रीनिंग की जा रही है. इसका उद्देश्य उन लोगों की पहचान करना है, जो अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संभावित खतरा हो सकते हैं. इस अतिरिक्त जांच के कारण वीजा प्रोसेसिंग टाइम पहले की तुलना में काफी बढ़ गया है. इस देरी का सबसे ज्यादा असर उन टेक्नोलॉजी कंपनियों पर पड़ रहा है, जो एच-1बी वीजा प्रोग्राम पर अत्यधिक निर्भर हैं. इस प्रोग्राम के तहत हर साल केवल 85,000 नए वीजा जारी किए जाते हैं. बिजनेस इनसाइडर द्वारा विश्लेषित डिपार्टमेंट ऑफ लेबर और यूएससीआईएस के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024 में गूगल ने 5,537 और एप्पल ने 3,880 एच-1बी वीजा के लिए आवेदन किए. जारी किए गए कुल एच-1बी वीजा में से 70 प्रतिशत से अधिक भारतीय नागरिकों को मिले, जिससे यह साफ है कि नई प्रक्रिया का सबसे बड़ा असर भारतीय आईटी पेशेवरों पर पड़ रहा है.

> इसका नतीजा यह हुआ है कि वीजा प्रोसेसिंग टाइम पुराने मानकों की तुलना में काफी बढ़ गया है. अमेरिकी टेक दिग्गज गूगल और ऐप्पल नौकरी वाले वीजा पर अमेरिका आये कर्मचारियों को देश छोड़ने से रोक रहे हैं. बिजनेस इनसाइडर ने एक ईमेल का हवाला देते हुए यह दावा किया है. इस रिपोर्ट के अनुसार, गूगल और ऐप्पल कुछ वर्क वीजा वाले कर्मचारियों को दूतावास में देरी के कारण अमेरिका से बाहर यात्रा न करने की सलाह दे रहे हैं. दोनों कंपनियों के बाहरी कानूनी सलाहकारों ने उन कर्मचारियों को ईमेल भेजे हैं जिन्हें अमेरिका में फिर से प्रवेश के लिए वीजा स्टैंप की जरूरत है. ऐसे कर्मचारियों को देश न छोड़ने की सलाह दी है क्योंकि वीजा प्रक्रिया में सामान्य से ज्यादा समय लग रहा है. रिपोर्ट में बताया गया है कि यह देरी अमेरिका आने वाले कुछ खास तरह के यात्रियों के लिए सोशल मीडिया वेरिफिकेशन की ज़रूरतों को लागू करने के कारण हो रही है. पिछले हफ्ते, एनबीसी ने एक अमेरिकी सीमा-शुल्क एवं सुरक्षा (सीबीपी) के दस्तावेज़ का हवाला देते हुए कहा था कि अमेरिकी अधिकारी देश में प्रवेश चाहने वाले विदेशी यात्रियों से पिछले पांच सालों का सोशल मीडिया डेटा मांगने की योजना बना रहे हैं. चैनल ने यह भी साफ किया कि सीबीपी आवेदकों के पिछले पांच सालों में इस्तेमाल किये गये फोन नंबर, ईमेल एड्रेस और परिवार के करीबी सदस्यों के बारे में विस्तृत जानकारी इकट्ठा करेगा.

न्याय विभाग से एप्स्टीन केस की फाइलें गायब

वेबसाइट से 16 दस्तावेज हटने पर ट्रंप और जांच एजेंसियों पर सवाल

वाशिंगटन, 21 दिसंबर. अमेरिका में कुख्यात फाइनेंसर और यौन तस्करी के आरोपी जेफरी एप्स्टीन से जुड़े मामले ने एक बार फिर सियासी और प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है.

अमेरिकी विधि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से एप्स्टीन केस से संबंधित कम से कम 16 अहम फाइलों के अचानक गायब हो जाने की खबर सामने आई है. यह घटनाक्रम ऐसे समय पर सामने आया है, जब हाल ही में कांग्रेस के दोनों दलों डेमोक्रेटिक पार्टी और कई रिपब्लिकन सांसदों के समर्थन से एक कानून के तहत एप्स्टीन मामले से जुड़ी कुछ सामग्री सार्वजनिक की गई थी. अमेरिकी विधि विभाग की वेबसाइट के उस विभाग से कम से कम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एप्स्टीन के साथ संबंध होने का संदेह है, हालांकि अभी तक कोई विशिष्ट सबूत पेश नहीं किया गया है कि अमेरिकी नेता बच्चों के यौन शोषण में शामिल थे.

एक रिपोर्ट के अनुसार, गायब फाइलों में नग्न महिलाओं की पेंटिंग की तस्वीरें शामिल थीं. साथ ही एक ऐसी तस्वीर भी गायब है जिसमें एक ड्रेसर और दराजों पर रखी तस्वीरों की एक श्रृंखला दिखाई गई थी, जिसमें एप्स्टीन, मेलानिया ट्रंप और एप्स्टीन की लंबे समय तक सहयोगी रही घिसलेन मैक्सवेल के साथ ट्रंप की एक तस्वीर भी शामिल थी.

> गौरतलब है कि एप्स्टीन पर 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका में सेक्स ट्रैफिकिंग और अपराध करने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था, जिसमें उसे 40 वर्षों से अधिक की जेल का सामना करना पड़ सकता था. अभियोजकों के अनुसार, 2002 और 2005 के बीच एप्स्टीन ने दर्जनों नाबालिग लड़कियों के साथ यौन संबंध बनाए, जिन्हें उसने न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा में अपने आवासों पर बुलाया था. वह उन्हें नकद भुगतान करता था और फिर कुछ पीड़ितों को और लड़कियों को लाने के लिए रिक्रूटर्स के रूप में नियुक्त करता था.

डीआरजी जवान की फायरिंग से मौत

नारायणपुर, 21 दिसंबर. छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले से एक दुखद घटना सामने आई है, जहां एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन से लौटते समय आकस्मिक फायरिंग में रविवार को डीआरजी के एक जवान की जान चली गई.

घटना के बाद पुलिस विभाग में शोक का माहौल है, वहीं जिले भर में इस हादसे को लेकर गहरी संवेदना व्यक्त की जा रही है. एसपी कार्यालय से आज प्राप्त आधिकारिक जानकारी के अनुसार 20 दिसंबर को नारायणपुर डीआरजी की एक टीम थाना छोटाडोंगर क्षेत्रांतर्गत एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन के लिए रवाना हुई थी. यह अभियान निर्धारित योजना के तहत संचालित किया गया, जिसमें किसी भी प्रकार की मुठभेड़ या असामान्य स्थिति की सूचना नहीं मिली. अभियान पूर्ण होने के बाद 21 दिसंबर की सुबह डीआरजी की टीम कैम्प कड़ेनार पहुंची. बताया गया कि अभियान समाप्ति के पश्चात जब डीआरजी के जवान वाहन में सवार हो रहे थे, उसी दौरान एक हथियार से आकस्मिक रूप से फायर हो गया. इस दुर्भाग्यपूर्ण फायरिंग में नारायणपुर डीआरजी में पदस्थ आरक्षक बलदेव सिंह हुर्रा के सिर के पास गोली लग गई.

महायुति का 288 में 215 सीटों पर कब्जा

महाराष्ट्र निकाय चुनाव में शिंदे-अजित पवार की पकड़ मजबूत

मुंबई/नई दिल्ली, 21 दिसंबर. महाराष्ट्र के नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में महायुति ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए राज्य की शहरी राजनीति में अपना वर्चस्व साबित कर दिया है.

कुल 288 सीटों में से महायुति गठबंधन ने 215 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि महाविकास अघाड़ी (एमवीए) महज 51 सीटों पर सिमट कर रह गई. इन नतीजों में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार गुट की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी कई क्षेत्रों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई.

> निकाय चुनावों के नतीजों ने राज्य की राजनीति में साफ संदेश दे दिया है. भाजपा-शिवसेना (शिंदे गुट)-एनसीपी (अजित पवार गुट) से बनी महायुति ने 288 में से 215 नगर परिषद और नगर पंचायतों पर जीत दर्ज कर विपक्ष को लगभग चारों खाने चित कर दिया. भाजपा अकेले 130 सीटों के साथ बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि शिंदे गुट को 51 और अजित पवार गुट को 33 सीटें मिलीं. क्षेत्रवार आंकड़ों पर नज़र डालें तो विदर्भ, मराठ वाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र और कोंकण चारों क्षेत्रों में महायुति ने बढ़त बनाई.

ध्यान से बढ़ी शांति व भावनात्मक कल्याण : उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन

नई दिल्ली, 21 दिसंबर. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने रविवार को विश्व ध्यान दिवस के मौके पर कहा कि भारत की आध्यात्मिक परंपरायें विश्व का मार्गदर्शन करती हैं.

उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने तेलंगाना के कान्हा शांति वनम में विश्व ध्यान दिवस के मौके पर आयोजित समारोह में मन की शांति, भावनात्मक कल्याण तथा सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने में ध्यान की शाश्वत प्रासंगिकता पर विशेष बल दिया. उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने सभा को संबोधित करते हुये कहा कि ध्यान एक सार्वभौमिक पद्धति है जो सांस्कृतिक, भौगोलिक और धार्मिक सीमाओं से परे है. उन्होंने

इसे मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक स्थिरता और आंतरिक परिवर्तन के मार्ग के रूप में वर्णित किया और इस बात पर जोर दिया कि विश्व ध्यान दिवस आधुनिक जीवन में चिंतन के बढ़ते महत्व को पहचानने का अवसर देता है. राधाकृष्णन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के उस प्रस्ताव को सह-प्रायोजित करने में भारत की भूमिका का उल्लेख किया.

उत्तराखंड के सभी स्कूलों में अब भगवद् गीता अनिवार्य

देहरादून. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य के सभी स्कूलों में अब भगवद् गीता के श्लोकों का पाठ अनिवार्य कर दिया गया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में मुख्यमंत्री धामी ने कहा- इस पहल का उद्देश्य छात्रों को भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों और जीवन दर्शन से जोड़ना है, ताकि उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा सके. हमारी सरकार ने राज्य के स्कूलों में गीता के श्लोकों का पाठ अनिवार्य किया है. गीता के उपदेश बच्चों में आत्मविश्वास, कर्तव्यबोध और सकारात्मक सोच विकसित करने में मदद करेंगे.

श्रम कल्याण कोष घोटाले का मालिक गिरफ्तार

▶ ईडी ने गुवाहाटी प्रिंटिंग प्रेस पर की कार्रवाई

नई दिल्ली, 21 दिसंबर. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुवाहाटी के पूर्बाश्री प्रिंटिंग हाउस के मालिक प्रियांशु बोइरागी को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया है.

एजेंसी के गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय ने रविवार को यह जानकारी दी. यह गिरफ्तारी बोइरागी के ठिकानों पर तलाशी अभियान के बाद हुई. एक विशेष पीएमएलए अदालत ने बोइरागी को पांच दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है. इस धनशोधन मामले की जांच असम के मुख्यमंत्री के विशेष सतर्कता

प्रकोष्ठ द्वारा भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की अलग-अलग धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी से शुरू हुई है. ईडी के एक अधिकारी ने बताया कि बोइरागी ने कथित तौर पर असम भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तत्कालीन सदस्य सचिव चोहान डोले एवं तत्कालीन अध्यक्ष गौतम बरुवा और दूसरे अधिकारियों के साथ मिलकर श्रम कल्याण उपकर के तौर पर जमा किए गए सरकारी फंड को धोखे से हड़पने की साज़िश रची. उन्होंने बताया कि निर्माण लागत के एक प्रतिशत की दर से जमा किया गया यह उपकर, पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए एक खास कोष है. यह दुर्घटना और मृत्यु , चिकित्सा सहायता , मातृत्व लाभ , पेंशन, शिक्षा सहायता जैसे अनेक फायदे के लिए होता है. अधिकारी ने बताया, घोटाले के साजिशकर्ताओं ने समाज के बहुत गरीब तबकों के लिए रखे गए कोष को धोखे से हड़प लिया और उसे वैध कर दिया. ईडी के मुताबिक, 2013-14, 2014-15 और 2015-16 वित्तीय वर्ष के दौरान बोइरागी को नकली और जाली टेंडर प्रक्रिया के ज़रिए कुल 121.05 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी वाले मुद्रण अनुबंध दिए गए.

राकांपा ने जीता ईश्वरपुर, जयंत पाटिल को मिला स्पष्ट बहुमत

सांगली, 21 दिसंबर. जयंत पाटिल के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) ने ईश्वरपुर नप चुनाव में स्पष्ट बहुमत के साथ जीत हासिल की है.

राकांपा (एसपी) ने 30 में से 23 सीटें जीतीं, जबकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले महायुति को सिर्फ सात सीटें मिलीं. राकांपा (एसपी) उम्मीदवार आनंदराव मालगुंडे नगर परिषद अध्यक्ष चुने गये. जीत के बाद राकांपा (एसपी) कार्यकर्ताओं ने ईश्वरपुर में पटाखे फोड़कर और गुलाल लगाकर जश्न मनाया. ईश्वरपुर में मुकाबला मुख्य रूप से महायुति और राकांपा (एसपी) के बीच था. सभी विपक्षी दल जयंत

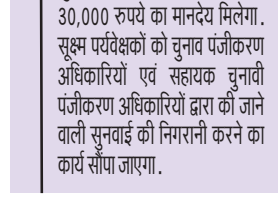

पाटिल के खिलाफ एकजुट हो गये थे. अध्यक्ष पद के चुनाव में आनंदराव मालगुंडे ने राकांपा (एसपी) की तरफ से चुनाव लड़ा, जबकि भाजपा ने पूर्व मंत्री अन्नासाहेब डांगे के बेटे विश्वनाथ डांगे को मैदान में उतारा था. इस बीच, सांगली के आस्था नगर परिषद में विशाल शिंदे राकांपा (एसपी) ने जीत हासिल की.

जी राम जी योजना मनरेगा के आगे का कदम

▶ कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी जानकारी

नई दिल्ली, 21 दिसंबर. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज विकसित भारत जी राम जी बिल को अपनी मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही अब ये कानून का रूप ले चुका है. इससे पहले केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक वक्तव्य जारी किया.

उन्होंने विकसित भारत जी राम जी एक्ट के बारे में विस्तार से बताया तथा कहा कि इसके बारे में भ्रम फैलाने की साजिश हो रही है. केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि मनरेगा के नाम पर फिर एक बार देश को गुमराह करने की साजिश हो रही है. भ्रम फैलाए जा

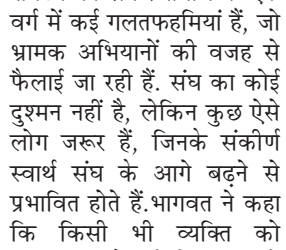

रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि विकसित भारत-जी राम जी योजना मनरेगा के आगे का कदम है. केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि मजदूर भाइयों, अब 100 नहीं, बल्कि 125 दिनों के काम की कानूनी गारंटी है. काम न मिलने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान को और सशक्त बनाया गया है. मजदूरी अगर देर से मिली तो अतिरिक्त राशि देने का भी प्रावधान किया गया है.

> विकसित भारत के लिए विकसित गांव, स्वावलंबी गांव और गरीबी मुक्त - रोजगार युक्त गांव बनाने के लिए जल संरक्षण, गांव में इन्फ्रास्ट्रक्चर के काम, आजीविका मूलक गतिविधियों तथा प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के काम हाथ में लिए जाएंगे. श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 125 दिन के रोजगार की गारंटी के साथ कृषि कार्य के समय छोटे-छोटे किसान भाई-बहनों को दिक्कत न हो, इसके लिए भी प्रावधान किया गया है. यह कानून गरीब के हक में है, विकास के हक में है और यह कानून मजदूरों को रोजगार देने की पूरी गारंटी है.

एक नजर में

कैलिफोर्निया में बिजली घर में लगी आग

सैन फ्रांसिस्को, 21 दिसंबर. अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में बिजली घर में आग लगने के कारण 130,000 से ज्यादा लोग अंधेरे में रह रहे हैं. यह खुलासा निगरानी सेवा पावर आउटेज के डेटा से हुआ है. डेटा के मुताबिक, 01:45 बजे तक कैलिफ़ोर्निया में 130,000 से ज़्यादा उपभोक्ता बिना बिजली के थे, जिनमें से 125,000 सैन फ़्रांसिस्को में हैं. सैन फ़्रांसिस्को के दमकल विभाग के अनुसार पीजी एंड ई निगम के सबस्टेशन में आग लग गयी है, और उसे बुझाने की कोशिशें चल रही हैं. सैन फ़्रांसिस्को के मेयर डेनियल लूरी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि बिजली जाने से सार्वजनिक परिवहन और यातायात लाइट पर असर पड़ा है. उन्होंने लोगों से बिजली वापस आने तक घर पर रहने की अपील की है.

अधूरे आश्वासनों से जनता में नाराजगी : रेड्डी

हैदराबाद/नई दिल्ली, 21 दिसंबर. कोयला और खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को एक खुला पत्र लिखा है, जिसमें 2023 तेलंगाना विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस के दिये गये आश्वासनों के क्रियान्वयन पर सवाल उठाये गये हैं. पत्र में श्री किशन रेड्डी ने हाल ही में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा प्रस्तुत तेलंगाना राइजिंग-2047 विजन डॉक्यूमेंट का जिक्र किया और श्रीमती सोनिया

गांधी द्वारा राज्य सरकार की दृष्टि एवं दो वर्ष के शासन की सराहना करने संबंधी मीडिया रिपोर्टों का उल्लेख किया. उन्होंने इसका विरोधाभास कांग्रेस के घोषणा-पत्र अभयहस्तम एवं चुनाव प्रचार के दौरान सार्वजनिक रूप से घोषित छह गारंटियों से जोड़ा, तथा पूछा कि क्या पार्टी नेतृत्व ने सत्ता में आने के बाद इनके क्रियान्वयन की समीक्षा की है.

जोहान्सबर्ग में बार में गोलीबारी में नौ की मौत

जोहान्सबर्ग. दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के बेकर्सडाल में एक मदिरालय(बार) में हुए हमले में दो महिलाओं समेत नौ लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य लोग घायल हैं. पुलिस के अनुसार लगभग 12 अज्ञात बंदूकधारी दो वाहनों में सवार होकर आए और बार में मौजूद लोगों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी. वे घटनास्थल से भागते समय भी लगातार फायरिंग करते रहे. ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग के अनुसार, यह गोलीबारी रविवार को स्थानीय समयानुसार लगभग दिन में एक बजे हुई. पुलिस ने बताया कि अभी तलाशी अभियान जारी है. गौरतलब है दक्षिण अफ्रीका दुनिया की सबसे अधिक हत्या दर वाले देशों में से एक है. पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, इस साल अप्रैल और सितंबर के बीच औसतन हर दिन 63 लोग मारे गए. यहां अक्सर बहस, डकैती और गिरोहों की आपसी हिंसा के कारण हत्याएं होती रहती हैं. इस हत्याकांड का हालांकि अभी मकसद स्पष्ट नहीं है.

बंगाल में केंद्रीय कर्मी बनेंगे सूक्ष्म पर्यवेक्षक

▶ मतदाता सूची की सुनवाई पर रखेंगे कड़ी निगरानी

कोलकाता, 21 दिसंबर. पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने केंद्रीय सरकारी एजेंसियों और राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ एक उच्च स्तरीय समन्वय बैठक की, ताकि राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की सुनवाई के दौरान सूक्ष्म पर्यवेक्षकों की तैनाती की जा सके.

सीईओ कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी चर्चा के दौरान उपस्थित थे. अधिकारियों के अनुसार, सभी 16 प्रतिभागी एजेंसियों एवं बैंकों ने इस अभ्यास के लिए अपने अधिकारियों को भेजने की इच्छा व्यक्त की है. एजेंसियों से रविवार तक मनोनीत अधिकारियों के नाम जमा करने

की अपेक्षा की गई है जिसके बाद सोमवार को नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे. चयनित अधिकारियों को बुधवार को एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होना होगा. चुनाव आयोग पूरे राज्य में लगभग 3,500 सूक्ष्म पर्यवेक्षकों की तैनाती करने की योजना बना रहा है.

वहीं सुनवाई के दौरान किसी भी अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए लगभग 4,000 से 4,500 अधिकारियों को रिजर्व रखने की तैयारी चल रही है.

> बैठक में कोल इंडिया, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, आयकर विभाग, सीजीएसटी, सीमा शुल्क, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय रिजर्व बैंक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक, कोलकाता स्थित यूको बैंक के क्षेत्रीय प्रमुख, मुख्य डाक महानिरीक्षक कार्यालय, डीएसपी, पूर्वी रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे, मेट्रो रेलवे, बाल्मर लॉरी, एलआईसी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ कई अन्य बैंकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. चुनाव आयोग पहले ही केंद्रीय सरकारी अधिकारियों को सूक्ष्म पर्यवेक्षकों के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे चुका है. जिसमें प्रत्येक अधिकारी को सुनवाई प्रक्रिया की निगरानी के लिए 30,000 रुपये का मानदेय मिलेगा. सूक्ष्म पर्यवेक्षकों को चुनाव पंजीकरण अधिकारियों एवं सहायक चुनावी पंजीकरण अधिकारियों द्वारा की जाने वाली सुनवाई की निगरानी करने का कार्य सौंपा जाएगा.

आज का इतिहास

1241- मंगोल के प्रमुख लेफ्टीनेंट बहादुर तैर हुलागु खान ने लाहौर पर क़ब्ज़ा किया.

1666 - गुरु गोविंद सिंह - सिक्खों के दसवें एवं अंतिम गुरु का जन्म.

1843 - रवीन्द्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज में शामिल हुए.

1851 - भारत में पहली मालगाड़ी चलाई गई. इसे रूड़की से चलाया गया.

1882 - थामस अल्वा एडिसन के बनाए गए बल्बों से पहली बार 'क्रिसमस ट्री' को सजाया गया और यह रोशनी से जगमगा उठा.

1910 - अमेरिका में पहली बार डाक बचत पत्र जारी किया.

1940 - एम नाथ राय ने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना का ऐलान किया.

आरएसएस को बीजेपी से जोड़ना भूल : मोहन भागवत

कोलकाता, 21 दिसंबर. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को आरएसएस के शताब्दी समारोह के मौके पर एक कार्यक्रम में भाग लिया. यह कार्यक्रम कोलकाता के साइंस सिटी ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया था.

यहां मोहन भागवत ने कहा कि संगठन को लेकर समाज के एक वर्ग में कई गलतफहमियां हैं, जो भ्रामक अभियानों की वजह से फैलाई जा रही हैं. संघ का कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लोग जरूर हैं, जिनके संकीर्ण स्वार्थ संघ के आगे बढ़ने से प्रभावित होते हैं. भागवत ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को आरएसएस के बारे में राय बनाने

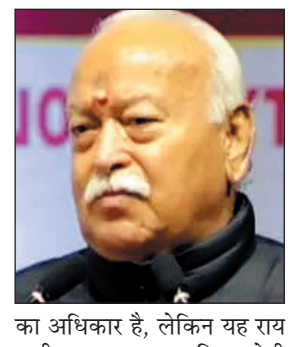

का अधिकार है, लेकिन यह राय हकीकत पर आधारित होनी चाहिए, न कि अफवाहों, बनाए गए नैरेटिव्स या द्वितीयक स्रोतों की जानकारी पर. उन्होंने बताया कि संघ की वास्तविकता लोगों के सामने लाने के लिए देश के चार शहरों कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में व्याख्यान और संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.

बदलाव | **टूरिस्ट सर्किट को 100-100 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा विकसित**

पर्यटन क्षेत्र में राजस्थान ने भरी नई उड़ान

जयपुर, 20 दिसम्बर. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकास भी, विरासत भी के मूल मंत्र के साथ राज्य सरकार ने गत दो वर्षों में प्रदेश के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक गौरव को और समृद्ध करते हुए पर्यटन उद्योग को नई पहचान दी है.

साथ ही यह भी सुनिश्चित किया है कि राजस्थान में पर्यटन के लिए आने वाले देशी- विदेशी पर्यटकों को स्तरीय सुविधाओं के साथ-साथ सुरक्षित और अच्छा वातावरण मिले और वे अपने साथ सुखद अनुभव लेकर जाएं. मुख्यमंत्री सीएम भजनलाल शर्मा

के नेतृत्व में राज्य में पर्यटन के विकास के लिए किये जा रहे सतत प्रयासों का परिणाम है कि वर्ष 2024 में देशी पर्यटकों की संख्या में 28.50 प्रतिशत तथा विदेशी पर्यटकों की संख्या में 21.92 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई. इसी प्रकार वर्ष 2025 में अगस्त माह तक, वर्ष 2024 की समान अवधि की तुलना में देशी एवं विदेशी पर्यटक यात्राओं में 11.71 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. प्रदेश में घूमने के लिए आने वाले मेहमानों को नए अनुभव प्रदान करने तथा हर उम्र के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन के विभिन्न आयामों को विकसित किया जा रहा है. हैरिटेज, धार्मिक, रूरल, एडवेंचर तथा ईको टूरिज्म के विकास के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है. प्रदेश में पर्यटन स्थलों के विकास, पर्यटकों की सुविधा के विस्तार तथा ब्रांडिंग के लिए 5 हजार करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्य कराए जाएंगे.

> इसके लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान टूरिज्म इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड का गठन किया गया है. पर्यटकों में राजस्थान के प्रति बढ़ते आकर्षण की बानगी है कि वर्ष 2025 में अगस्त तक राज्य में 15 करोड़ से अधिक देशी पर्यटक तथा लगभग 12 लाख विदेशी पर्यटक राजस्थान आए हैं. वर्ष 2024 की देशी व विदेशी पर्यटक यात्राओं में देश में राज्य को 5 वीं रैंक प्राप्त हुई है.

चंडीगढ़ में 1.14 करोड़ रुपए का प्राइवेट ग्रांट सेल घोटाला उजागर

चंडीगढ़ 21 दिसंबर. चंडीगढ़ के पीजीआई में 1.14 करोड़ रुपये के प्राइवेट ग्रांट सेल घोटाले की परतें अब तेजी से खुलती जा रही हैं जांच में सामने आया है कि यह फर्जीवाड़ा केवल एक विभाग तक सीमित नहीं था, बल्कि इससे पहले भी सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं में करोड़ों रुपये की अनियमितताएं की जा चुकी थीं.

अधिकारियों के अनुसार आयुष्मान भारत और हिमकेयर योजना में हुए घोटालों का मास्टरमाइंड भी वही व्यक्ति था, जिसने पीजीआई के प्राइवेट ग्रांट सेल में बड़ा खेल किया. जांच एजेंसियों ने खुलासा किया है कि घोटाले का मुख्य आरोपी दुर्लभ कुमार अपने कुछ साथियों और पीजीआई के कर्मचारियों की मिलीभगत से यह पूरा नेटवर्क चला रहा था. आरोप है कि उसने डॉक्टरों और विभागाध्यक्षों की फर्जी मुहरें बनवाकर अमृत फार्मेसी से महंगी दवाएं मुफ्त में निकलवाईं. इन दवाओं का उद्देश्य जरूरतमंद मरीजों को लाभ पहुंचाना था, लेकिन इन्हें अवैध रूप से बाजार में बेच दिया गया. बताया जा रहा है कि आरोपी इन दवाओं को चंडीगढ़ के नामी केमिस्टों को 10 से 20 प्रतिशत कम कीमत पर सप्लाई करता था, जिससे उसे मोटा मुनाफा होता था. इस पूरे मामले में पीजीआई के कुछ कर्मचारियों की संलिप्तता भी सामने आई है.